जी.आर.पी . की भूमिका

अपने अधिकार क्षेत्र के, क्षेत्रों के संबंध में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्तव्य सामान्य रूप से उनके प्रभार के क्षेत्रों में जिला पुलिस के समान हैं। राजकीय रेलवे पुलिस के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष कर्तव्य हैं:
(i) रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। शब्द "आदेश" कर्तव्यों में शामिल हैं: -
ए) स्टेशन परिसर के भीतर यात्री यातायात का नियंत्रण, विशेष रूप से प्लेटफॉर्म पर, बुकिंग कार्यालयों में, प्रतीक्षालय में, प्रवेश और निकास द्वार पर और जहां भी स्टेशन के अधिकारियों द्वारा आपात स्थिति में विशेष रूप से आवश्यक हो;
बी) स्टेशन परिसर में वाहनों और अन्य यातायात का नियंत्रण;
सी) स्टेशनों पर रुकी पैसेंजर ट्रेनों में व्यवस्था बनाए रखना और गाड़ियों में अतिरिक्त भीड़ की रोकथाम करना ;
डी) स्टेशन पर खड़ी लोडेड पैसेंजर ट्रेनों का पर्यवेक्षण;
इ) उपद्रव करने के दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, पीड़ित व्यक्तियों को हटाना
संक्रामक रोग और स्टेशन परिसर को भिखारियों से दूर रखना;
एफ) यात्रीयो द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के लिए और गाड़ियों का निरीक्षण यह देखने के लिए कि फिटिंग से कोई छेड़ छाड नहीं की गई है, टर्मिनल स्टेशनों पर पहुंचने वाली खाली गाड़ियों की जांच करना

जी) बीमार यात्रियों का अस्पताल पहुँचाना और ट्रेनों में या स्टेशन परिसर में मरने वाले व्यक्तियों के शवों को हटाना और परिवहन करना

(ii) रेलवे अधिनियम के तहत अपराधों को रेलवे या सिविल के उचित अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए, और रेलवे कर्मियों की ओर से धोखाधड़ी या उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए;
(iii) रेलवे पर दुर्घटनाओं की जांच करना;
(iv) रेलवे अधिकारियों और यात्रा करने वाली जनता को जहां तक संभव हो, सहायता प्रदान करना
ऐसी सहायता प्रदान करना पुलिस अधिकारियों के रूप में अपने स्वयं के कर्तव्यों के अनुकूल है।

रेलवे पर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए आम तौर पर सरकारी रेलवे पुलिस जिम्मेदार होती है। स्टेशनों और पार्सल कार्यालयों में माल-डिब्बों, माल-डिब्बों की सुरक्षा का कर्तव्य रेलवे पुलिस का नहीं, बल्कि रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल का है।

आर.पी.एफ और रेल अधिनियम में संशोधन के बाद जी.आर.पी. के कर्तब्य इस प्रकार है।

ए) देश के 36,600 जी.आर.पी कर्मी अपना ध्यान जघन्य अपराधों खासकर ट्रेनों में बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों पर केंद्रित कर सकेंगे।
बी) जी.आर.पी जहां रेलवे के लिए पुलिसिंग करना जारी रखेगी, वहीं उसे जघन्य अपराधों की जांच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और समय मिलेगा।
सी) जी.आर.पी का उपयोग रेल अधिनियम की धारा 150, 151 और 152 में परिभाषित तोड़फोड़ के मामलों में ट्रैक पेट्रोलिंग और प्रभावी जांच के लिए किया जा सकता है।

——-oOo——